पंजाब राज्य एवं अन्य

बनाम

कुलदिप सिंह

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482:

अधिसूचना- सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी कार्रवाई के पीड़ित को विशेष अनुग्रह राशि-मुआवजे की मांग हेतु धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका दायर- प्रतिवादी-पीड़ित को राहत और चिकित्सा खर्च दिए गए. -उच्च न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता को 80,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

अपील पर निर्धारित- अधिसूचना अनुसार सिमित विशेष अनुग्रह राशि ही आतंकवादी कार्यवाही के पीडित को सुरक्षा बलों द्वारा दी जाती है- अत: पीड़ित अधिसूचना की शर्तो के अनुरूप नियत सीमा से अधिक राशि की मांग नही कर सकता है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का दावा धारा 482 के अधीन गलत है। इसके अलावा पीड़ित को राज्य सरकार द्वारा रोजगार भी दिया गया है- हालाँकि भुगतान किया गया चिकित्सा व्यय सामान्य व्यय

की तुलना में न्यून है- तदनुरूप, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि अधिसूचना की शर्तो के अनुरूप भुगतान की जा चुकी अनुग्रह राशि के अतिरिक्त चिकित्सा व्यय के पेटे 17,000/- का भुगतान करे।

उत्तरदाता 7.7.1993 पर आतंकवादी का पीछा करने की कार्यवाही के दौरान घात लगा कर हुए हमले के दौरान घायल हो गया था जब वह रात में एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। पुलिस ने कई गोलियां चलानी शुरू कर दीं, उसकी दाहिनी भुजा पर लगी, जो उड़ गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां कोहनी के नीचे का दाहिना हाथ काट दिया गया। इसके बाद उन्हें एक और सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि उन्हें फोड़ा हो गया था। उन्हें एक लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि दी गई। 20, 000/- नागरिक शक्ति में कार्य करने वाले सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी कार्रवाई के पीड़ितों को अनुग्रह राशि और चिकित्सा खर्च के रूप में 3,378/- रुपये की राशि प्रदान करने वाली अधिसूचना के संदर्भ में।लगभग 10 वर्षों के बाद, उन्होंने 3 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए धारा 482 Cr.P.C के तहत एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 80,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि देकर याचिका को स्वीकार कर लिया।इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि भुगतान की गई राशि अधिसूचना के संदर्भ में निर्धारित की गई थी, इसलिए भुगतान के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है।

प्रतिवादी-पीड़ित ने प्रस्तुत किया कि राशि विशुद्ध रूप से उपशामक उपाय के रूप में दी गई थी और इसलिए, मुआवजा देने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था; और यह कि चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई राशि छोटी है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया-

1.राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.1.1991 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि इसका भुगतान "विशेष अनुग्रह अनुदान"के रूप में किया गया था।सीमा भी तय की गई थी। इसलिए, उत्तरदाता द्वारा अधिक राशि के लिए अधिसूचना के संदर्भ में कोई दावा करने का सवाल ही नहीं उठता है।इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी एक रिट याचिका में मुआवजे का दावा नहीं कर रहा था, बल्कि धारा 482 Cr.P.C के तहत था, और इस तरह की धारणा गलत है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने के 10 साल बाद दावा किया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी को एक सरकारी स्कूल में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसलिए सख्ती से स्पष्ट है की, अधिसूचना के संदर्भ में प्रतिवादी को आगे कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना है। लेकिन भुगतान किए गए चिकित्सा खर्च निश्चित रूप से सामान्य खर्चों की तुलना में कम हैं जो ऑपरेशन और उपचार के लिए खर्च किए गए प्रतीत होते हैं। तदनुसार, राशि रुपये 20,000/- नियत है। यह अधिसूचना के तहत अनुग्रह मुआवजे के रूप में पहले से ही भुगतान की गई निश्चित राशि के अतिरिक्त है। हालांकि एक विलंबित दावा किया गया, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, विलंबित कार्यवाही को घातक नहीं माना जाता है।तदनुसार, 17000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दो महीने के भीतर प्रत्यर्थी को किया जावे।[पैरा 7]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2002 की सिविल अपील सं. 1295

आपराधिक विविध मामले में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.05.2002 के निर्णय और आदेश से। 2001 का सं. 25991-एम।

अपीलार्थियों की ओर से गंगनदीप शर्मा और अजय पाल।

प्रत्यर्थी की ओर से जी. कॉलिन गोंजाल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्योति मेंदिरत्ता।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा-

1.पंजाब राज्य और उसके पदाधिकारी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं। दण्ड प्रकिया सहिंता की धारा 482 के अधीन प्रस्तुत याचिका पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से अपीलार्थी-राज्य को अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त Rs.80,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह प्रत्यर्थी के दावे के अंतिम निपटारे में होगा।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

जुलाई 1991 में पंजाब राज्य चरम आतंकवाद के कब्जे में था।उत्तरदाता को गोली लगी और उसकी अग्र-भुजा के ऊपर का हाथ काटना पड़ा।पंजाब सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग, चंडीगढ़ के सचिव ने राज्य में उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों (सी) को नागरिक शक्ति के अधीन काम करने वाले सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी कार्रवाई के परिणामस्वरूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत के संशोधित पैमाने के बारे में लिखा।

3. इसमें निम्नलिखित प्रावधान किया गया थाः

"नागरिक शक्ति की सहायता में कार्य करने वाले आतंकवादी हिंसा/सुरक्षा बलों में 100% से कम स्थायी विकलांगता बनाए रखने वालों को विशेष अनुग्रह राशि देने का सवाल इस विभाग के समक्ष सक्रिय विचाराधीन था

और यह निर्णय लिया गया कि नागरिक शक्ति की सहायता में कार्य करने वाले सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी हिंसा में 100% से कम अक्षमता बनाए रखने वाले निर्दोष नागरिक की स्थिति में, उन्हें निम्नलिखित पैमाने पर विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकता हैः

25 प्रतिशत तक की अक्षमता की स्थिति में 5,000/- रुपये। 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अक्षमता की स्थिति में Rs.10,000 तक। 50 प्रतिशत से अधिक और 100% -से कम विकलांगता की स्थिति में Rs.20,000।

4. 7.7.1991 पर आतंकवादी का पीछा करने के दौरान घात लगा कर हुए हमले में प्रतिवादी घायल हो गया था।वह रात में एक रिश्तेदार से मिलने गया था।पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा।पुलिस बलों के अनुसार उसने वाहन रोकने पर कोई ध्यान नहीं दिया। एसी स्थिति में पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, कई गोलियां उनकी दाहिनी भुजा में लगीं जो तुरंत उड़ गई और ऊपरी भुजा से अलग हो गई।उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां कोहनी के नीचे का दाहिना हाथ काट दिया गया।इसके बाद भी प्रतिवादी को पीजीआई, चंडीगढ़ में एक और सर्जरी करानी पड़ी क्योंकि उसे फोड़ा हो गया था।उसे अधिसूचना के संदर्भ में Rs.20,000/- का भुगतान किया गया था और चिकित्सा खर्च के रूप में 3,378/- रुपये की राशि दी गई थी। लगभग 10 वर्षों के बाद, धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका दायर की गई थी जिसमें 3 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।विलंबित

दृष्टिकोण और धारा 482 Cr.P.C की गैर-प्रयोज्यता सहित कई आधारों पर दावे का विरोध किया गया।

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

दाखिल किए गए जवाब को रिकॉर्ड में लिया गया।

पंजाब राज्य याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि में Rs.80,000/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा।यह याचिकाकर्ता के दावे का अंतिम निपटान होगा।

याचिका का उसी के अनुसार निपटारा किया जाता है।

5. अपील के समर्थन में, राज्य और उसके अधिकारियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भुगतान की गई राशि अधिसूचना के संदर्भ में निर्धारित की गई थी और इसलिए, भुगतान के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश स्पष्ट रूप से अरक्षणीय है।

6. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि राशि विशुद्ध रूप से उपशामक उपाय के रूप में दी गई थी और इसलिए, मुआवजा देने की उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सा खर्चों के लिए दी गई राशि बहुत कम है।

7. दिनांकित 18.1.1991 अधिसूचना पर एक नज़र डालने मात्र से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि इसका भुगतान "विशेष अनुग्रह अनुदान" के रूप में

किया गया था।सीमा भी तय की गई थी। इसलिए, उत्तरदाता द्वारा अधिक राशि के लिए अधिसूचना के संदर्भ में कोई दावा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी एक रिट याचिका में मुआवजे का दावा नहीं कर रहा था, बल्कि धारा 482 Cr.P.C के तहत, जो की गलत है ।इसके अतिरिक्त, यह दावा सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने के 10 साल बाद किया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी को एक सरकारी स्कूल में चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।इसलिए, स्पष्ट है कि , अधिसूचना के संदर्भ में प्रतिवादी को आगे कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना है।लेकिन हम पाते हैं कि भुगतान किए गए चिकित्सा खर्च निश्चित रूप से सामान्य खर्चों की तुलना में कम हैं जो ऑपरेशन और उपचार के लिए खर्च किए गए प्रतीत होते हैं।हम क्वांटम को Rs.20,000/- पर तय करते हैं।यह अधिसूचना के तहत अनुग्रह मुआवजे के रूप में पहले से ही भुगतान की गई निश्चित राशि के अतिरिक्त है।हालाँकि दावा देर से किया गया था, लेकिन मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए हमने देर से प्रस्तुत करने को घातक नहीं माना है।उत्तरदाता को दो महीने के भीतर Rs.17,000/- की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जावे। उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

एसकेएस.

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।